राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल पीठ दीवानी रिट याचिका संख्या 18980/2017

हरि सिंह पुत्र रामलाल, ए-37, महारानी एन्क्लेव, हस्थसाल, उत्तम नगर, नई दिल्ली।

---- अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार को सचिव, गृह ,राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. अपर महानिदेशक (आरएसी), जयपुर, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
3. महानिरीक्षक (आरएसी), जयपुर, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
4. कमांडेंट 12वीं बटालियन, आरएसी (आईआर), तृतीय डीएपी, पुलिस लाइन, विकासपुरी, नई दिल्ली 18।
5. सहायक कमांडेंट (एसी), 12वीं बटालियन आरएसी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
6. संयुक्त सचिव (अपील), गृह (समूह 11) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

---- प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री राम कुमार स्वामी, सलाहकार।
साथ श्री राकेश कुमार स्वामी, सलाहकार।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री पी.एस. नरुका, सलाहकार। की ओर से
श्री रूपिन काला, शासकीय. परामर्शदाता.

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

आदेश

20/09/2023

रिपोर्टेबल

1. अपीलार्थी द्वारा तत्काल रिट याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप-पत्र दिनांक 14.09.2007, सजा आदेश दिनांक 31.03.2008, अपीलीय आदेश दिनांक 10.02.2009 को चुनौती देते हुए विभागीय अपील को खारिज कर दिया गया है और आदेश दिनांक 25.05.2017 द्वारा अपीलार्थी दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है, संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलार्थी को दिनांक 13.04.1995 के आदेश के तहत राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी 'सी' कंपनी, 12वीं बटालियन आरएसी (आईआर) चाण्क्यपुरी, नई दिल्ली में तैनात था और उसे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) 1958 नियमों के नियम 16 के तहत जारी दिनांक 14.09.2007 को आरोप-पत्र दिया गया था। (इसके बाद '1958 के नियम')।

3. अपीलार्थी ने दलील दी है कि आरोपों के बयान के साथ ज्ञापन अपीलार्थी के ससुर द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पर आधारित था जिसमें झूठे आरोप थे कि अपीलार्थी के किसी मुकेश कुमारी के साथ अवैध संबंध थे।

4. अपीलार्थी ने दलील दी है कि आरोपों के ज्ञापन से पता चला है कि अपीलार्थी की शादी सुलोचना के साथ हुई थी और विवाह से दो बच्चे पैदा हुए थे। अपीलार्थी का एक कांस्टेबल-मुकेश कुमारी, जो नई दिल्ली में सीआरपीएफ में कार्यरत थी, के साथ अवैध संबंध था और वह पहले से ही एक विवाहित महिला थी। अपीलार्थी अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध में रह रहा था और वह अपनी विधिक रूप से विवाहित पत्नी और बच्चों से नहीं मिलता था। अपीलार्थी ने अपने ससुराल वालों के समझाने के बावजूद, अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाए रखा और अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करने पर ध्यान नहीं दिया। उक्त कृत्य को अनैतिक जीवन जीने का गंभीर कदाचार और अनुशासनहीनता का कार्य भी माना गया।

5. अपीलार्थी ने दलील दी है कि आरोप-पत्र प्राप्त होने के बाद, उसने दिनांक 21.09.2007 और 28.09.2007 के आवेदनों के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया था। चूंकि, अपीलार्थी को उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रदान नहीं की गई थी, जिनके आधार पर आरोप तय किए गए थे और आगे, उन्हें निर्धारित समय के भीतर निरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया था और इस तरह, अपीलार्थी जवाब दाखिल करने में सक्षम नहीं था।

6. अपीलार्थी ने दलील दी है कि दस्तावेजों की कुछ अधूरी, अपठनीय, अप्रासंगिक और अप्रमाणित फोटोकॉपी निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उसे उपलब्ध कराई गईं।

7. अपीलार्थी ने 09.10.2007 को सभी दस्तावेजों की पूर्ण और सुपाठ्य प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए फिर से एक आवेदन किया था और अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था।

8. अपीलार्थी ने अनुरोध किया है कि यद्यपि दिनांक 04.10.2007 के आदेश द्वारा अभ्यावेदन दाखिल करने की समय सीमा दस दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी, तथापि, दस्तावेजों की प्रति की आपूर्ति के बिना यह अर्थहीन था।

9. अपीलार्थी ने दलील दी है कि उसने विभागीय जांच के लिए अपने प्रतिनिधित्व और बचाव की तैयारी के लिए 30 दिनों की विशेषाधिकार छुट्टी देने के लिए विभिन्न आवेदन अर्थात 14.08.2007, 28.09.2007 और 09.10.2007 को दायर किए थे, हालांकि, अनुरोध था स्वीकार नहीं किया गया और समय नहीं बढ़ाया गया।

10. अपीलार्थी ने दलील दी है कि उसने एक सहायक अधिकारी नियुक्त करने का भी अनुरोध किया था लेकिन उसी प्रार्थना को भी बिना किसी कारण के खारिज कर दिया गया था।

11. अपीलार्थी ने दलील दी है कि प्रत्यार्थियों के मनमाने और असंवैधानिक कृत्य के कारण, अपीलार्थी को मानसिक बीमारी के साथ संकट और मानसिक पीड़ा हुई। बताया जाता है कि अपीलार्थी ने कुछ स्थानीय साधन लिया और उसके बाद नई दिल्ली में मनोचिकित्सा विभाग के डॉक्टर से भी परामर्श लिया

12. अपीलार्थी ने दलील दी है कि उसके लिए अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना और समझना असंभव है और इस तरह, वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है।

13. अपीलार्थी ने दलील दी है कि आरोप-पत्र के खिलाफ खुद को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना, प्रत्यार्थियों ने अपीलार्थी को दंडित करने के लिए पूर्व-निर्धारण के साथ मनमाने ढंग से एक जांच अधिकारी नियुक्त किया।

14. अपीलार्थी ने दलील दी है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उसे सेवा से बर्खास्त करते हुए दिनांक 31.03.2008 को एक पक्षीय आदेश पारित किया था। अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि जांच रिपोर्ट की प्रति, पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों की प्रतियां और पूछताछ के दौरान प्रदर्शन के रूप में चिह्नित दस्तावेजों की प्रतियां

प्रदान किए बिना सजा आदेश पारित किया गया था।

15. अपीलार्थी ने आगे आरोप लगाया है कि सजा देने से पहले उसे प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

16. अपीलार्थी ने दलील दी है कि उसने बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ विभागीय अपील दायर की और अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 10.02.2009 के आदेश द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिए और बिना दिमाग लगाए अपील खारिज कर दी। ।

17. अपीलार्थी ने दलील दी है कि 1958 के नियमों के नियम 34 के तहत एक समीक्षा याचिका उसके द्वारा दायर की गई थी और उसे राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के समक्ष रखे बिना भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है।

18. अपीलार्थी ने आगे दलील दी है कि उसे पता चला है कि अपीलार्थी के साथ अवैध संबंध रखने के समान आरोप में नई दिल्ली में सीआरपीएफ के कार्यालय में काम करने वाली मुकेश कुमारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी और उसे दोषमुक्त कर दिया गया था। झूठे, तुच्छ और परेशान करने वाले आरोपों के कारण वह अभी भी सीआरपीएफ की सेवा में हैं।

19. अपीलार्थी ने दलील दी है कि वह आरएसी द्वारा संचालित कैंटीन में तैनात था और वह अन्य कर्मचारियों के संपर्क में था, जो कैंटीन में आते थे और इस तरह, अपीलार्थी एक सेवा प्रदाता होने के नाते, ग्राहक के रूप में कर्मचारियों और कई कर्मचारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करता था। अपीलार्थी के साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से अपनी समस्याएं साझा करते थे और मुकेश कुमारी भी उनमें से एक थी लेकिन अपीलार्थी का कोई गलत इरादा या अवैध संबंध नहीं था।

20. अपीलार्थी ने दलील दी है कि उसकी शादी श्रीमती सुलोचना के साथ हुई थी और वे खुशी से रहते थे और वह भी नई दिल्ली में उसके साथ रहने आई थी। अपीलार्थी का ससुर अपनी पत्नी को गुमराह करता था और वह अपीलार्थी को दिल्ली से अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरित करना चाहता था, हालांकि, प्रत्यर्थी ने इस तरह के झूठे आरोपों का दुरुपयोग किया और बिना सोचे-समझे अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी।

21. अपीलार्थी ने यह भी दलील दी है कि अपीलार्थी की पत्नी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसके तहत अपीलार्थी पहले से ही 2,000/- रुपये प्रति माह का गुजारा भत्ता दे रहा था। और बाद में चूंकि रखरखाव को

बढ़ाकर 5,000/- रुपये कर दिया गया था और इसका भुगतान भी उनके द्वारा किया गया था।

22. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही और सजा आदेश को चुनौती देते हुए निम्नलिखित दलीलें दीं: -

22.1 अपीलार्थी के खिलाफ किसी अन्य विवाहित महिला के साथ अवैध संबंध रखने के आरोपों का मूल आधार विभागीय जांच में कार्यवाही के लिए कदाचार नहीं हो सकता है। व्यभिचारी जीवन जीने का अपराध अब आईपीसी के तहत अपराध नहीं है और केवल सक्षम आपराधिक न्यायालय ही ऐसे अपराध की सुनवाई कर सकता था, लेकिन यह विभागीय जांच का विषय नहीं हो सकता है।

22.2 अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे और इस प्रकार, आरोप-पत्र जारी करने का मूल आधार ही कानून की नजर में दोषपूर्ण है।

22.3 अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने बिना सोचे-समझे और सजा आदेश अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है।

22.4 इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई दस्तावेजी या मौखिक सबूत नहीं था कि अपीलार्थी किसी अन्य विवाहित महिला के साथ अवैध संबंध में रह रहा था और केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ आरोप साबित नहीं किए जा सकते थे।

22.5 अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों को साबित पाए जाने के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कारण नहीं बताया है।

22.6 जिस महिला (मुकेश कुमारी) के खिलाफ अपीलार्थी के साथ रहने का आरोप लगाया गया है, उसके पति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है और दूसरी पत्नी के पति द्वारा शिकायत के अभाव में, अपीलार्थी पर अनैतिक जीवन जीने का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। अपीलार्थी की पत्नी ने भी कोई शिकायत नहीं की और केवल अपीलार्थी की पत्नी के पिता ने शिकायत की थी

22.7 अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों को पहले ही भरण-पोषण का भुगतान कर दिया गया था और इस प्रकार, उनका भरण-पोषण न करने का आरोप पूरी तरह से निराधार और बिना किसी दिमाग के प्रयोग के था।

22.8 अपीलार्थी के खिलाफ की गई कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर

उल्लंघन थी और अपीलार्थी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी और इसे कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

22.9 अपीलार्थी के खिलाफ आरोप-पत्र तामील होने के बाद भी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप है, अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी और अपीलार्थी को चिकित्सा कारणों से सेवा से अनुपस्थित रहना पड़ा और इस तरह, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने गलत तरीके से अपनी राय तैयार की।

22.10 अपीलार्थी को जारी आरोप-पत्र में ही अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए पूर्व निर्धारण दिखाया गया है और इस प्रकार, पूरी विभागीय जांच दूषित हो गई है।

22.11 अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति दी गई और उसके अभाव में सजा आदेश टिकाऊ नहीं है।

22.12 अपीलार्थी पर लगाई गई सज़ा कठोर और अनुपातहीन है

23. प्रत्यार्थियों ने रिट याचिका का उत्तर दाखिल कर दिया है।

24. प्रत्यार्थियों ने दलील दी है कि अपीलार्थी के खिलाफ उसके ससुर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि अपीलार्थी का एक महिला कांस्टेबल मुकेश कुमारी के साथ अवैध संबंध था और अपीलार्थी अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं कर रहा था और अपीलार्थी का ऐसा कृत्य था। यह स्पष्ट रूप से अनैतिकता, घोर कदाचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

25. प्रत्यार्थियों ने दलील दी है कि अपीलार्थी को दिनांक 21.09.2007 और 29.09.2007 को आवेदन प्राप्त होने के बाद आरोप-पत्र का उत्तर दाखिल करने का उचित अवसर दिया गया था और इस प्रकार, सहायक कमांडेंट को अगले दस दिनों के लिए समय बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। अपीलार्थी को कार्य दिवस पर कमांडेंट के कार्यालय से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी और अपीलार्थी को ये दस्तावेज 08.10.2007 को प्राप्त हुए थे।

26. प्रत्यार्थियों ने रिकॉर्ड (अनुलग्नक-आर/1) पर रखा है जहां अपीलार्थी ने बयानों और अन्य दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने के लिए अपने हस्ताक्षर किए थे।

27. प्रत्यार्थियों ने दलील दी है कि अपीलार्थी को ऐसे दस्तावेज प्राप्त होने के बावजूद, उसने अपना उत्तर दाखिल नहीं किया और उसने उत्तर दाखिल करने के लिए फिर से समय बढ़ाने की मांग की।

28. प्रत्यार्थियों ने आदेश दिनांक 15.10.2007 (अनुलग्नक-आर/2) के माध्यम से फिर से पांच दिन का समय बढ़ाया।

29. प्रत्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने के आधार पर अपीलार्थी पक्ष द्वारा उत्तर दाखिल करने से इनकार को रिकॉर्ड पर रखा है और अपीलार्थी ने 27.10.2007 को आगे समय मांगा है।

30. प्रत्यार्थियों ने दलील दी है कि चूंकि अपीलार्थी ने विस्तारित समय के भीतर उत्तर दाखिल नहीं किया और जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। 09.10.2007 और इस प्रकार, दिनांक 05.11.2007 के आदेश द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था और उसी की प्रति अपीलार्थी को दी गई थी और उसे अपने बचाव प्रतिनिधि का नाम और पता देने के लिए कहा गया था। दिनांक 05.11.2007 के आदेश की प्रति सहायक कमांडेंट 'सी' कंपनी के माध्यम से अपीलार्थी को सेवा के लिए भेजी गई थी लेकिन अपीलार्थी अपने निवास पर नहीं मिला और उसके बाद विशेष के माध्यम से अपीलार्थी के नए पते पर एक पत्र भेजा गया था संदेशवाहक, हालांकि, अपीलार्थी वहां नहीं मिला और ऐसे में, जब अपीलार्थी से उसके मोबाइल फोन पर संपर्क किया गया, तो उसने बताया कि वह हिसार (हरियाणा) में था और इस प्रकार, जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिनांक 05.11.2007 की प्रति, अनुलग्नक-आर/3 के रूप में संलग्न किया गया है।

31. प्रत्यार्थियों ने दलील दी है कि अपीलार्थी को फिर से अपने बचाव प्रतिनिधि का नाम देने के लिए कहा गया था और अपीलार्थी को उसके आवासीय (गांव) पते पर पंजीकृत डाक से एक पत्र भेजा गया था और अपीलार्थी वहां नहीं मिला और उसके परिवार के सदस्यों को नोटिस लेने और अपीलार्थी का पता देने से इनकार कर दिया।

32. प्रत्यार्थियों ने बचाव प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए दिनांक 25.01.2008 को फिर से एक पत्र भेजा और चूंकि अपीलार्थी दिए गए पते पर नहीं मिला, इसलिए प्रत्यार्थियों ने 12.02.2008 को समाचार-पत्रों अर्थात पंजाब केसरी (दिल्ली संस्करण) में और 10.02.2008 को माहभारती, राजस्थान (जयपुर संस्करण) में एक नोटिस प्रकाशित किया, जिसमें अपीलार्थी को दस दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने और अपने बचाव प्रतिनिधि को नियुक्त करने और अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। जांच अधिकारी को एकपक्षीय कार्यवाही करनी थी। उत्तरदाताओं ने इन सभी दस्तावेजों और पेपर प्रकाशनों को अनुलग्नक-आर/5 और आर/6 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा है।

33. प्रत्यार्थियों ने अनुरोध किया है कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित नोटिस के बावजूद अपीलार्थी 09.10.2007 से लगातार अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहा और इस प्रकार, वह न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ और न ही बचाव प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए अपना उत्तर और आवेदन प्रस्तुत किया।

34. प्रत्यार्थियों ने दलील दी है कि अपीलार्थी द्वारा मानसिक रोग से पीड़ित होने की दलील भी गलत है, क्योंकि अपीलार्थी के पास कोई चिकित्सा अवकाश लेने या सरकारी चिकित्सा संस्थान में अपना इलाज कराने के बारे में अधिकारियों को सूचित करने का कोई समय नहीं था।

35. प्रत्यार्थियों ने दलील दी है कि जांच अधिकारी ने मौखिक और दस्तावेजी सबूतों को ध्यान में रखते हुए जांच की और उन्होंने पाया कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। जांच रिपोर्ट अपीलार्थी को दिनांक 10.03.2008 के कारण बताओ नोटिस के साथ भेजी गई थी, जिसमें अपीलार्थी के अभ्यावेदन या उसके खिलाफ लगाए जाने वाले जुर्माने के खिलाफ उत्तर मांगा गया था। अपीलार्थी अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा और अपीलार्थी को उक्त नोटिस के लिए उचित सेवा दी गई, जिसे जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ अपीलार्थी को भेजा गया था।

36. प्रत्यार्थियों ने दलील दी कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करते हुए जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हुए और सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाते हुए दिनांक 31.03.2008 को आदेश पारित किया।

37. प्रत्यार्थियों ने दलील दी है कि जुर्माने के आदेश की प्रति अपीलार्थी के दिल्ली और उसके गांव के पते पर भी चिपकाई गई थी और इस प्रकार, अपीलार्थी को दिनांक 30.04.2008 का नोटिस नहीं मिला, इसलिए इसे दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका दिनांक 16.05.2008 और दैनिक समाचार पत्र नवभारत टाइम्स, दिल्ली दिनांक 18.05.2008 में भी प्रकाशित किया गया था।

38. प्रत्यार्थियों ने अनुरोध किया है कि गंभीर प्रयास करने के बाद, दिनांक 31.03.2008 के आदेश की प्रति अपीलार्थी को 02.07.2008 को विशेष दूत के माध्यम से दी गई थी और उसी की रिपोर्ट भी अनुलग्नक-आर/11 के रूप में दायर की गई है।

39. प्रत्यार्थियों ने दलील दी है कि अपीलार्थी द्वारा उठाई गई शिकायत पर गौर करते समय अपीलीय प्राधिकारी को अपील स्वीकार करने का कोई आधार नहीं मिला और इस

तरह, अपील खारिज कर दी गई।

40. प्रत्यार्थियों ने दलील दी है कि अपीलार्थी की समीक्षा याचिका को भी समीक्षा प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है।

41. प्रत्यर्थी श्री पी.एस. नरूका की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर आए हैं, वे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अपीलार्थी अनैतिक जीवन जी रहा था और आरोप-पत्र की तामील के बाद से ड्यूटी से अनुपस्थित था। इसके अलावा, अपीलार्थी ने सामान्य मोड के साथ-साथ विशेष मोड द्वारा सेवा प्रदान करने के बावजूद न तो विभागीय जांच में भाग लिया और न ही वह सभी चरणों में प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ।

42. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अनैतिक जीवन जीना राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के तहत परिभाषित एक गंभीर कदाचार है।

43. अपीलार्थी के मामले की जांच विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा की गई है और मामले के वर्तमान तथ्यों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुशासनात्मक मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है।

44. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है, जो निम्नानुसार हैं: -

1. महेश चंद शर्मा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2067/1999 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 27.11.2018 द्वारा पारित आदेश।

2. वित्त मंत्रालय और अन्य बनाम एस.बी. रमेश [एआईआर 1998 सुप्रीम कोर्ट 853] में रिपोर्ट किया गया।

3. केशरीमल बनाम राजस्थान सरकार [1978 आरएलडब्ल्यू राजस्थान 599] में रिपोर्ट किया गया।

4. **छीतरमल बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य (1997) 1 डब्लूएलसी (राज.) 734]**। में रिपोर्ट किया **गया।**

5. **भारत संघ एवं अन्य बनाम ज्ञानचंद चत्तर [(2009) 12 एससीसी 78]** में

रिपोर्ट किया गया।

6. **अनिल गिलुरकर बनाम बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य [(2011)14 एससीसी 379]** में रिपोर्ट किया।

7. **इलाहाबाद बैंक एवं अन्य बनाम कृष्ण नारायण तिवारी [(2017) एआईआर एससी 330]** में रिपोर्ट किया गया।

8. **क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम मसूद अहमद खान और अन्य [(2010)9 एससीसी 496]** में रिपोर्ट किया।

9. **भारत संघ एवं अन्य बनाम दीनानाथ शांताराम कारेकर और अन्य [(1998) एआईआर एससी 2722]** में रिपोर्ट किया गया।

10. **यूपी सरकार बनाम मो. शरीफ (मृत) एल.आर.एस. के माध्यम से, [(1982) एआईआर एससी 937]** में रिपोर्ट किया गया।

45. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. नरूका ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है, जो इस प्रकार हैं:-

1. **भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम नरेंद्र कुमार पांडे [(2013)2 एससीसी 740]** में रिपोर्ट किया गया।

2. **कर्नाटक सरकार और अन्य बनाम उमेश को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1763-1764/2022 में 22.03.2022** को निर्णय दिया गया।

3. **जोनल मैनेजर, यूको बैंक एवं अन्य बनाम कृष्ण कुमार भारद्वाज [(2022)5 एससीसी 695]** में रिपोर्ट किया गया।

4. **उप महाप्रबंधक (अपीलीय प्राधिकारी) एवं अन्य बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव ने [(2021)2 एससीसी 612]** में रिपोर्ट किया गया।

5. **भारत संघ और अन्य बनाम पी. गुणसेकरन ने [(2015)2 एससीसी 610]** में रिपोर्ट किया गया।

6. **बैंक ऑफ इंडिया बनाम अपूर्व कुमार साहा की रिपोर्ट [(1994)2 एससीसी 615]**।

7. **लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम पं. राम सरूप और अन्य [(1957)**

एआईआर एससी 82] में रिपोर्ट किया गया।

8. **जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया** ने **[(2023) लाइव लॉ (एससी) 117]** में रिपोर्ट किया गया।

46. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

47. यह न्यायालय 1971 के नियमों के नियम 3, 3ए और 4 को उद्धृत करना उचित समझता है, जो इस प्रकार हैं:-

> **3. सामान्य**.- (1) प्रत्येक सरकारी सेवक हर समय--
>
> (i) पूर्ण अखंडता बनाए रखेगा; और
>
> (ii) कर्तव्य के प्रति समर्पण और पद की गरिमा बनाए रखेगा।
>
> (2) (i) पर्यवेक्षी पद धारण करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने नियंत्रण और अधिकार के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों की कर्तव्य के प्रति निष्ठा और समर्पण सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा;
>
> (ii) कोई भी सरकारी सेवक, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में या उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अलावा अन्यथा कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जब वह ऐसे निर्देश के तहत कार्य कर रहा हो, तो जहां भी व्यावहारिक हो, लिखित में निर्देश प्राप्त करें। और जहां लिखित में निर्देश प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है, वहां उसे उसके बाद यथाशीघ्र निर्देश की लिखित पुष्टि प्राप्त करनी होगी।
>
> स्पष्टीकरण- उप-नियम (2) के खंड (ii) में कुछ भी सरकारी कर्मचारी को किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करके या अनुमोदन प्राप्त करके अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सशक्त बनाने के रूप में गठित नहीं किया जाएगा, जब शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण की योजना के तहत ऐसे निर्देश आवश्यक नहीं हैं।
>
> **3A** नियमों का उल्लंघन: कोई भी सरकारी कर्मचारी जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(i) अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान या नहीं, नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

4. अनुचित एवं अशोभनीय आचरण – कोई भी सरकारी कर्मचारी जो –

(i) अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान या नहीं, नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया

(ii) सार्वजनिक रूप से अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करता है जो एक सरकारी कर्मचारी के रूप में उसकी स्थिति के अनुरूप नहीं है;

(iii) यह साबित हो गया है कि उसने किसी प्राधिकारी व्यक्ति को गुमनाम या छद्म नाम से याचिका भेजी है;

(iv) अनैतिक जीवन जीता है;

(v) वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश या निर्देशों की अवज्ञा करता है या वरिष्ठ अधिकारी की अवहेलना करता है;

(vi) बिना पर्याप्त और उचित कारण के, अपने पति या पत्नी, माता-पिता, नाबालिग या विकलांग बच्चे के भरण-पोषण की उपेक्षा करता है या इनकार करता है, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है या, उनमें से किसी की भी जिम्मेदार तरीके से देखभाल नहीं करता है;

(vii) बिजली और पानी जैसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने वाले किसी भी विभाग/कंपनियों को वित्तीय नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से मीटर या किसी अन्य उपकरण या बिजली/पानी की लाइन के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना;

—अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

48. इस न्यायालय ने 1971 के नियमों के नियम 3 के अवलोकन पर पाया कि सरकारी कर्मचारी 1971 के नियमों के नियम 3 (1) (ii) के अनुसार हर समय कर्तव्य के प्रति समर्पण और पद की गरिमा बनाए रखते हुए कार्य करेगा।

49. इस न्यायालय ने पाया कि 1971 के नियमों के नियम 3ए के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी 1971 के नियमों का उल्लंघन करता है, तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

50. इस न्यायालय ने पाया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो अनैतिक जीवन जीता है,

1971 के नियमों के नियम 4 के उप-नियम (iV) के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

51. इस न्यायालय ने पाया कि 'कदाचार' शब्द को 1971 के नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। सेवा न्यायशास्त्र में 'कदाचार' शब्द का अपना अर्थ है और सेवा प्रदान करते समय प्रत्येक कमीशन या चूक, कदाचार की श्रेणी में नहीं आ सकती है। यह न्यायालय, स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोष में दी गई 'कदाचार' की परिभाषा को उद्धृत करना उचित समझता है, जहां 'कदाचार' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

> "दुर्व्यवहार का अर्थ है, बुरे उद्देश्य से उत्पन्न दुराचार; लापरवाही के कार्य, निर्णय की त्रुटियां, निर्दोष गलती, ऐसे कदाचार का गठन नहीं करते हैं।"

52. 'कदाचार' शब्द को ब्लैक विधि शब्दकोश में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

> "एक निषिद्ध कार्य, कर्तव्य से अपमान, गैरविधिक व्यवहार, चरित्र में जानबूझकर, अनुचित या गलत व्यवहार।" अपराध में कदाचार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के कर्तव्यों के संबंध में कोई भी गैरविधिक व्यवहार, जानबूझकर चरित्र। इन शर्तों में ऐसे कार्य शामिल हैं जिन्हें करने का कार्यालय-धारक को कोई अधिकार नहीं था, अनुचित तरीके से किए गए कार्य और कार्य करने में विफलता वास्तव में कार्य करने के लिए एक सकारात्मक कर्तव्य है।"

53. 'कदाचार' शब्द को पी. रमानाथ अय्यर का लॉ लेक्सिकन, पुनर्मुद्रित संस्करण 1987 पृष्ठ 821 पर में भी निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

> "कदाचार शब्द का तात्पर्य गलत इरादे से है, न कि केवल निर्णय में त्रुटि से। कदाचार आवश्यक रूप से नैतिक अधमता से जुड़े आचरण के समान नहीं है। कदाचार शब्द एक सापेक्ष शब्द है और इसकी व्याख्या उस विषय-वस्तु और संदर्भ के आधार पर की जानी चाहिए जिसमें कदाचार होता है। यह शब्द अधिनियम के दायरे या कद को ध्यान में रखते हुए होता है, जिसका अर्थ लगाया जा रहा है। कदाचार का शाब्दिक अर्थ गलत आचरण या अनुचित आचरण है। सामान्य बोलचाल में, कदाचार का अर्थ है कार्रवाई के कुछ स्थापित और निश्चित नियम का उल्लंघन, जहां कोई

> विवेक नहीं बचा है, सिवाय इसके कि आवश्यकता क्या मांग सकती है और लापरवाही, लापरवाही और अकुशलता कार्रवाई के कुछ स्थापित, लेकिन अनिश्चित नियम का उल्लंघन है, जहां कुछ विवेक आवश्यक है नायक पर छोड़ दिया गया. कदाचार निश्चित कानून का उल्लंघन है, लापरवाही है, किसी कार्य का निषिद्ध गुण है और आवश्यक रूप से अनिश्चित है, कार्यालय में कदाचार को सार्वजनिक अधिकारी द्वारा गैरविधिक व्यवहार या उपेक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे किसी पार्टी के अधिकार प्रभावित हुए हैं।"

54. इस न्यायालय को मुख्य रूप से अपीलार्थी द्वारा अनैतिक जीवन जीने के कृत्य को एक सरकारी कर्मचारी के कदाचार या अशोभनीय आचरण में से एक के रूप में विचार करने की आवश्यकता है जहां एक विवाहित महिला के साथ रहने, उसके साथ अवैध संबंध रखने और उक्त के साथ व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। महिला, अपनी पत्नी के रूप में और इस तरह अनैतिक जीवन जी रही है और अनुशासनहीनता भी दिखा रही है।

55. यह न्यायालय पाता है कि 1971 के नियमों के नियम 4 के उप-नियम (iV) के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अनैतिक जीवन जीता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति किसी विवाहित महिला के साथ उसकी इच्छा के अनुसार रहने का दावा कर सकता है, उसे अपने पति से कोई आपत्ति नहीं है और यह अनैतिक जीवन जीने के समान नहीं होगा। दूसरा प्रश्न एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपना व्यक्तिगत जीवन अपनी पसंद के अनुसार जीने की स्वतंत्रता का दावा करने के संबंध में है, यदि समाज को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि क्या उसका नियोक्ता उसे अनैतिक जीवन न जीने के लिए बाध्य कर सकता है।

56. इस न्यायालय ने पाया कि 1971 के नियमों के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को न केवल कर्तव्य के प्रति समर्पण और पद की गरिमा बनाए रखनी है बल्कि उसे आचार संहिता का पालन करना है और किस तरीके से न केवल अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है बल्कि अपनी ड्यूटी के घंटों के अलावा या कार्यालय में काम न करते समय, उसे नियोक्ता द्वारा निर्धारित मानदंडों/आचरण नियमों का पालन करना होगा।

57. यह न्यायालय पाता है एक सरकारी कर्मचारी एक लोक सेवक है और ऐसी स्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, ऐसे कर्मचारी को निजी और साथ ही सार्वजनिक जीवन में उच्च मानकों को बनाए रखना होता है और उसे बोर्ड से ऊपर रहना होता है।

उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित मानदंडों या आचरण नियमों का पालन न करके सरकारी कर्मचारी को अपने निजी जीवन में अपने अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

58. सरकारी कर्मचारी के नियोक्ता के साथ कर्मचारी का संबंध निजी चरित्र का नहीं है, जहां केवल दो व्यक्तिगत व्यक्ति नियोक्ता और कर्मचारी के रूप में उनके रिश्ते को नियंत्रित कर रहे हैं।

59. सरकारी सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यालय में या कार्यालय समय के बाद भी कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। आम जनता की नजर में वह एक जनसेवक हैं. एक सरकारी कर्मचारी को अपने कार्यालय के कर्तव्य-समय से अपने निजी जीवन को अनैतिक जीवन जीने के तरीके से अलग करने की स्थिति को ऐसे सरकारी कर्मचारी के पक्ष में निरंकुश अधिकार प्रदान करके नहीं माना जा सकता है।

60. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि अपीलार्थी के खिलाफ किसी अन्य विवाहित महिला के साथ अवैध संबंध रखने के आरोप का मूल आधार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए कदाचार नहीं हो सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ के मामले में पारित निर्णय [(2019) 3 एससीसी 39]** में रिपोर्ट किए गए अनुसार व्यभिचारी जीवन जीना अब आईपीसी के तहत अपराध नहीं है। ।

61. इस न्यायालय ने पाया कि **जोसेफ शाइन (सुप्रा.)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका के माध्यम से आईपीसी की धारा 497 की वैधता तय करने के लिए कहा गया था।

62. सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करने वाली आईपीसी की धारा 497 को संवैधानिक रूप से रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सौमित्रि विष्णु बनाम के पहले के फैसलों को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने [1985 के एससीसी 137] में रिपोर्ट किए गए सौमित्री विष्णु बनाम भारत संघ और [(2012) एससीसी 358] में रिपोर्ट किए गए वी रेवती बनाम भारत संघ [(1988)2 एससीसी 72] और डब्ल्यू कल्याणी बनाम सरकार के पहले फैसलों को भी खारिज कर दिया।

63. **जोसेफ शाइन** (सुप्रा.) के मामले में पारित निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के पांच माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिया गया था और जबकि 5वें माननीय न्यायमूर्ति अन्य

माननीय न्यायाधीशों से सहमत थे, तथापि, माननीय सुश्री न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने सहमति जताते हुए इस बात पर भी विचार किया कि क्या व्यभिचार को आपराधिक दंड या वैवाहिक गलतता के अधीन एक दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए जो तलाक के लिए एक वैध आधार है। माननीय न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि भले ही यौन बेवफाई नैतिक रूप से गलत आचरण हो सकता है, लेकिन आपराधिक मंजूरी के कारण किसी रिश्ते को अपराधी बनाने के लिए यह पर्याप्त शर्त नहीं हो सकती है, इसे उचित ठहराया जा सकता है, जहां गलत में कोई सार्वजनिक तत्व हो, जैसे कि सरकार सुबचाव के विरुद्ध अपराध और इसी तरह के अपराध। ये सार्वजनिक गलतियाँ हैं जहाँ पीड़ित कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समुदाय होता है। निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ (इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति के अनुसार) को निम्नानुसार उद्धृत करना उचित होगा: -

> "280. मुद्दा यह बना हुआ है कि क्या 'व्यभिचार' को आपराधिक प्रतिबंधों के अधीन एक दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए, या वैवाहिक ग़लती जो तलाक के लिए एक वैध आधार है।
>
> 280.1. एक दृष्टिकोण यह है कि परिवार समाज की मूलभूत इकाई है, यदि इसे बाधित किया जाता है, तो यह स्थिरता और प्रगति को प्रभावित करेगा। इसलिए, विवाह संस्था को संरक्षित करने में सरकार का वैध सार्वजनिक हित है। हालाँकि, व्यभिचार दो वयस्कों द्वारा सहमति से किया गया एक कृत्य हो सकता है, फिर भी यह पीड़ित-रहित अपराध नहीं है। यह विवाह की पवित्रता और जीवनसाथी के अपने साथी की वैवाहिक निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह समाज को प्रभावित करता है क्योंकि यह परिवार की मूल इकाई को तोड़ देता है, जिससे न केवल व्यभिचारी और व्यभिचारिणी के जीवनसाथियों को चोट पहुंचती है, बल्कि यह बच्चों, परिवार और सामान्य रूप से समाज के विकास और कल्याण को भी प्रभावित करता है, और इसलिए इसे अवश्य ही प्रभावित करना चाहिए। पूरे इतिहास में, सरकार ने विवाह संस्था में विनियमन के एक क्षेत्र को लंबे समय तक बरकरार रखा है। सरकार ने एक वयस्क के विवाह करने की आयु निर्धारित करके, विवाह संस्था के विभिन्न पहलुओं को विनियमित किया है; यह विवाह को विधिक

मान्यता प्रदान करता है; यह विरासत और उत्तराधिकार के संबंध में अधिकार बनाता है; यह न्यायिक अलगाव, गुजारा भत्ता, वैवाहिक अधिकारों की बहाली जैसे साधन प्रदान करता है; यह सरोगेसी, गोद लेने, बच्चे की हिरासत, संरक्षकता, विभाजन, बच्चे की संरक्षकता और कल्याण; माता-पिता की जिम्मेदारी को नियंत्रित करता है। ये सभी निजी हित के क्षेत्र हैं जिनमें सरकार का वैध हित बरकरार है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो समग्र रूप से समाज और सार्वजनिक कल्याण से संबंधित हैं। व्यभिचार का प्रभाव न केवल सहमति से दो वयस्कों के बीच विवाह को ख़तरे में डालता है, बल्कि बच्चों के विकास और नैतिक ताने-बाने को भी प्रभावित करता है। इसलिए सरकार का इसे आपराधिक अपराध बनाने में वैध सार्वजनिक हित है।

280.2. इसके विपरीत दृष्टिकोण यह है कि व्यभिचार एक वैवाहिक गलती है, जिसके केवल नागरिक परिणाम होने चाहिए। आपराधिक दंड के साथ दंडनीय कोई भी गलत कार्य, समग्र रूप से समाज के खिलाफ एक सार्वजनिक गलत होना चाहिए, न कि केवल एक व्यक्तिगत पीड़ित के खिलाफ किया गया कार्य। किसी निश्चित आचरण को अपराध घोषित करना यह घोषित करना है कि यह एक सार्वजनिक गलती है जो सार्वजनिक निंदा को उचित ठहराएगा, और इस तरह के नुकसान और गलत काम के खिलाफ आपराधिक मंजूरी के उपयोग की गारंटी देगा। जीवन के सबसे अंतरंग स्थानों में अपनी कामुकता के संबंध में अपनी पसंद चुनने की किसी व्यक्ति की स्वायत्तता को आपराधिक मंजूरी के माध्यम से सार्वजनिक निंदा से संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे निर्णय लेने की व्यक्ति की स्वायत्तता, जो पूरी तरह से व्यक्तिगत हैं, व्यक्ति के 'सर्वोत्तम हित' में कथित कार्रवाई करने के लिए सरकार के किसी भी हस्तक्षेप के प्रतिकूल होगी।

280.3 एंड्रयू एशवर्थ और जेरेमी हॉर्डर ने 'आपराधिक कानून के सिद्धांत' शीर्षक से अपनी टिप्पणी में कहा है कि अपराधीकरण का पारंपरिक प्रारंभिक बिंदु 'नुकसान सिद्धांत' है जिसका सार यह है कि

सरकार द्वारा ऐसे आचरण को अपराध घोषित करना उचित है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। लेखकों का मानना है कि अपराधीकरण के तीन तत्व हैं: (i) नुकसान, (ii) गलत काम, और (iii) सार्वजनिक तत्व, जिन्हें सरकार द्वारा किसी गलत कार्य को आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत करने से पहले साबित करना आवश्यक है।

280.4 जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि "एक सभ्य समुदाय के सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का उचित प्रयोग करने का एकमात्र उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकना है।

280.5 दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है अधर्म। एंड्रयू सिमेस्टर और एंड्रियास वॉन हिर्श का मानना है कि अपराधीकरण की एक आवश्यक शर्त यह है कि आचरण एक नैतिक गलती है। भले ही यौन बेवफाई नैतिक रूप से गलत आचरण हो, लेकिन इसे अपराध मानने के लिए यह पर्याप्त शर्त नहीं हो सकती है।

281. मेरे विचार में, आपराधिक मंजूरी को उचित ठहराया जा सकता है जहां गलती में कोई सार्वजनिक तत्व हो, जैसे सरकार सुबचाव के खिलाफ अपराध, और इसी तरह। ये सार्वजनिक गलतियाँ हैं जहाँ पीड़ित कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा समुदाय होता है।

281.1 व्यभिचार निस्संदेह जीवनसाथी और परिवार के लिए एक नैतिक गलती है। मुद्दा यह है कि क्या आम तौर पर समाज में गलतता का पर्याप्त तत्व मौजूद है, ताकि इसे आपराधिक कानून के दायरे में लाया जा सके?

281.2 सार्वजनिक निंदा का तत्व, अपराधी को दंडात्मक परिणाम देना और व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करना, केवल तभी उचित होगा जब समाज ऐसे आचरण से सीधे प्रभावित हो। वास्तव में, जहां किसी अपराध के लिए कारावास की सजा हो, वहां अधिक मजबूत औचित्य की आवश्यकता होती है।

281.3 सरकार को व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पसंद चुनने की स्वायत्तता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, अपराधों के अपराधीकरण में

न्यूनतम दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए।

281.4 गरिमा के साथ जीने के अधिकार में सरकार द्वारा सार्वजनिक निंदा और दंड का शिकार न होने का अधिकार शामिल है, सिवाय इसके कि जहां बिल्कुल आवश्यक हो। यह निर्धारित करने के लिए कि किस आचरण के लिए आपराधिक मंजूरी के माध्यम से सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या नागरिक उपाय उद्देश्य की पूर्ति करेगा। जहां किसी गलत कार्य के लिए नागरिक साधन पर्याप्त है, वहां सरकार द्वारा आपराधिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

282. उपरोक्त चर्चा और धारा 497 की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर पैरा 11 में बताया गया है, यह घोषित किया जाता है कि:

282.1 धारा 497 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक मानकर रद्द किया जाता है।

282.2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198(2) जिसमें भारतीय दंड संहिता के अध्याय XX के तहत अभियोजन की प्रक्रिया शामिल है, केवल उस सीमा तक असंवैधानिक होगी जहां तक यह धारा 497 के तहत व्यभिचार के अपराध पर लागू होती है।

282.3 इसके द्वारा सौमित्री विष्णु (सुप्रा.), वी. रेवती (सुप्रा.) और डब्लू. कल्याणी (सुप्रा.) के निर्णयों को खारिज कर दिया जाता है।"

64. इस न्यायालय ने पाया कि ***जोसेफ शाइन*** (सुप्रा.), विविध के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए भारत संघ की ओर से आवेदन संख्या 2204/2020 दायर किया गया था, क्योंकि भारत संघ को सेना अधिनियम, 1950 की धारा 45 और 63 धाराओं में निहित प्रावधानों के संबंध में ***जोसेफ शाइन*** (सुप्रा.) के निर्णय के प्रभाव पर विचार करना था।

65. सर्वोच्च न्यायालय ने ***जोसेफ शाइन*** (सुप्रा.) के मामले में निर्धारित अनुपात को

ध्यान में रखने के बाद स्पष्ट किया कि उक्त निर्णय सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम या वायु बल अधिनियम या अधिनियमों के कोई अन्य प्रावधान में प्रासंगिक प्रावधानों के प्रभाव और संचालन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था, यह न्यायालय कथित विविध आवेदन में पारित आदेश के प्रासंगिक अनुच्छेद पैरा उद्धृत करना उचित समझता है:-

> "(23) विचाराधीन मामले में यह न्यायालय केवल धारा 497 आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 198 (2) की वैधता से संबंधित था (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित)। इस न्यायालय ने अलग-अलग लेकिन समवर्ती निर्णयों के माध्यम से बात की। इस न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के प्रमुख निर्णय के अलावा, और जिनके साथ माननीय न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने सहमति व्यक्त की, अन्य विद्वान न्यायाधीशों ने अलग-अलग राय लिखी। हालांकि, वे इस बात से सहमत थे कि धारा 497 आईपीसी और धारा 198 सीआरपीसी असंवैधानिक थे। जिस आधार पर इस प्रावधान को निरस्त किया गया था, वह यह था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। इस मामले में, इस न्यायालय के पास विचाराधीन अधिनियमों के प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था। वास्तव में, हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस न्यायालय ने व्यभिचार को मंजूरी दी है। इस न्यायालय ने पाया है कि व्यभिचार एक नैतिक गलत हो सकता है (माननीय सुश्री न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के अनुसार)।
>
> (24) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में अधिनियमों की योजना इस न्यायालय के विचार के लिए नहीं आई, हमें आवश्यक रूप से निरीक्षण करना और स्पष्ट करना चाहिए कि इस न्यायालय का निर्णय जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2019) 3 एससीसी 39 उन अधिनियमों में प्रासंगिक प्रावधानों के प्रभाव और संचालन से बिल्कुल भी चिंतित नहीं था जो आवेदक द्वारा हमारे सामने रखे गए हैं। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय

ने न तो कहा और न ही इसने 1950 अधिनियम की धारा 45 और 63 के प्रभाव के साथ-साथ अन्य अधिनियमों या अधिनियमों के किसी भी अन्य प्रावधान के संबंधित प्रावधानों पर फैसला देने का साहस किया है।

(25) हम केवल इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं और विविध आवेदन का निपटान करते हैं। लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा।"

66. स्पष्टीकरण आवेदन में सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त आदेश यह स्पष्ट करता है कि यदि प्रासंगिक नियमों में कर्मचारी और नियोक्ता के संबंधों को नियंत्रित करने का प्रावधान है और जहां कुछ कृत्यों को कदाचार माना जाता है या यदि किसी व्यक्ति पर नेतृत्व करने का आरोप लगाया जाता है अनैतिक जीवन, आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करना, व्यभिचार के क़ानून पर कोई अपराध शेष नहीं है, वही नियोक्ता को किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा, यदि उसके खिलाफ अनुचित या अशोभनीय आचरण का आरोप लगाया गया है। यह न्यायालय यह भी पाता है कि कुछ कार्य 'आपराधिक' नहीं हो सकते हैं, हालाँकि, नागरिक गलतियाँ हैं।

67. इस न्यायालय का मानना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यभिचारी जीवन जीने के आरोप के परिणामस्वरूप कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, हालाँकि, यदि वही कार्य आचरण नियमों के विरुद्ध है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का नियोक्ता का अधिकार नहीं छीना जा सकता है।

68. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने ***महेश चंद शर्मा*** (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित एक निर्णय पर भरोसा जताया है। इस न्यायालय ने उक्त निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और पाया है कि समन्वय पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ व्यभिचारी जीवन जीने या कोई अवैध संबंध रखने के आरोप के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ की हैं। समन्वय पीठ ने भारतीय पौराणिक कथाओं को हटाकर यहां तक कि देवी-देवताओं का उदाहरण देकर भी टिप्पणी की है। समन्वय पीठ ने आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित कुछ रीति-रिवाजों और बहुविवाह को दुनिया के कुछ हिस्सों में आम होने का भी हवाला दिया है।

69. इस न्यायालय ने आगे पाया कि समन्वय पीठ ने निजता के अधिकार पर भी चर्चा की है और इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से और समाज के दृष्टिकोण से भी देखा गया है।

व्यभिचार की अवधारणा की व्याख्या विवाहित महिला या अविवाहित पुरुष के साथ व्यक्ति को पुरुष या महिला के साथ संबंध बनाने की स्वतंत्रता देकर की गई है; । इस न्यायालय ने पाया कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति की उक्त टिप्पणियाँ बिल्कुल गलत हैं, संदर्भ और किसी भी तर्क से रहित और किसी भी विधिक न्यायशास्त्र द्वारा समर्थित नहीं हैं।

70. इस न्यायालय ने पाया कि निर्धारित आचरण नियमों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर एक सरकारी कर्मचारी को अनैतिक जीवन जीने से रोकने के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं का हवाला देकर उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कानून को संहिताबद्ध किया गया है और नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने यदि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ आचरण नियमों को निर्धारित किया है, तो उसे अन्य देशों में प्रचलित रीति-रिवाजों या भारतीय पौराणिक कथाओं के संदर्भ से बाहर के संदर्भ में परीक्षण नहीं किया जा सकता है।

71. इसके अलावा, इस न्यायालय ने पाया कि समन्वय पीठ भी इस तथ्य से प्रभावित थी कि व्यभिचार के अपराध को असंवैधानिक करार दिया गया है और इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने ***नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ*** (रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 76/2016), जहां निजता के अधिकार को बरकरार रखा गया था, के मामले में एक आदेश पारित किया।

72. इस न्यायालय ने पाया कि ***महेश चंद शर्मा*** (सुप्रा.) के मामले में विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों को समान परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और इस प्रकार, ***वित्त मंत्रालय और अन्य*** (सुप्रा.) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपनी पूर्ण अस्वीकृति व्यक्त की थी। उपरोक्त निर्णय में ट्रिब्यूनल द्वारा की गई टिप्पणियों को निम्नानुसार उद्धृत करना प्रासंगिक होगा: -

> "यद्यपि यह आदर्श होगा यदि यौन संबंध विधिक विवाह तक ही सीमित हो, हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यौन संबंध को विधिक विवाह तक सीमित रखता हो, हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो अलग-अलग लिंग के दो वयस्क व्यक्तियों के बीच यौन संबंध बनाता हो, गैरविधिक है जब तक कि रिश्ता व्यभिचारी या अनैतिक न हो। यदि कोई पुरुष और महिला एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और यदि ऐसे

> निवास पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है, तो उनके बीच क्या होता है, यह उनके नियोक्ता की चिंता का विषय नहीं है। ऐसे जीवन को यदि समाज द्वारा बिना किसी नाराजगी या द्वेष के स्वीकार कर लिया जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि उनके जीवन में कोई नैतिक अधमता शामिल है। इस मामले में, ऐसा कोई मामला नहीं है कि आवेदक श्रीमती के.आर. अरुणा के साथ रह रहा हो, आम जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई है या जनता उनके आचरण को अनैतिक मानने लगी है। इसलिए, भले ही यह आरोप तथ्यात्मक हो कि आवेदक जो पहले से ही किसी अन्य महिला से शादी कर चुका है, श्रीमती के.आर. अरुणा के साथ रह रहा है की बात सच साबित हुई है। हमारा मानना है कि अकेले इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराएगा कि आवेदक कदाचार का दोषी है और विभागीय कार्रवाई और सजा का हकदार है।"

यह न्यायालय प्रासंगिक पैरा 8 को भी उद्धृत करता है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त के साथ अपनी पूर्ण अस्वीकृति दर्ज की है। ट्रिब्यूनल की टिप्पणियों को पैरा 8 में इस प्रकार उद्धृत किया गया है:-

> "तुरंत हम उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपनी पूर्ण अस्वीकृति दर्ज करते हैं। हम मामले से संबंधित तथ्यों के आधार पर दिए गए ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों के संदर्भ में गुण-दोष के आधार पर अपना निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं।

तथ्यों पर पूर्वोक्त निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि इस आरोप को साबित करने के लिए सबूतों की पूरी तरह कमी थी कि अपराधी एक सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित तरीके से रह रहा था या उसने इस तरह के जीवन से व्यभिचारी आचरण का प्रदर्शन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर पाया कि ऐसे कर्मचारी के खिलाफ की गई जांच पूरी तरह से असंतोषजनक थी और आरोप साबित करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और इस प्रकार, अनुशासनात्मक जांच के निष्कर्ष टिकाऊ नहीं थे।

73. उक्त निर्णय किसी भी तरह से यह तर्क नहीं देता है कि यदि अनैतिक जीवन/व्यभिचारी जीवन जीने वाले किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाया

जाता है, तो वह विभागीय जांच का विषय नहीं हो सकता है।

74. सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब सरकार और अन्य बनाम राम सिंह पूर्व-कांस्टेबल** के **[(1992) 4 एससीसी 54]** में रिपोर्ट किए गए मामले में बताया कि कदाचार करने से संबंधित कानून निर्धारित किया गया है। यह न्यायालय उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा संख्या 6, 7 और 8 को उद्धृत करना उचित समझता है, जो इस प्रकार हैं: -

> "6. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 'दुराचार' शब्द हालांकि सटीक परिभाषा में सक्षम नहीं है, प्रतिबिंब पर संदर्भ, इसके प्रदर्शन में अपराध और अनुशासन और कर्तव्य की प्रकृति पर इसका प्रभाव से इसका अर्थ प्राप्त होता है। इसमें नैतिक पतन शामिल हो सकता है, यह अनुचित या गलत व्यवहार होना चाहिए; गैरकानूनी, चरित्र में जानबूझकर; निषिद्ध कार्य, कार्रवाई के स्थापित और निश्चित नियम या आचार संहिता का उल्लंघन लेकिन केवल निर्णय की त्रुटि, लापरवाही या कर्तव्य के प्रदर्शन में लापरवाही नहीं; अधिनियम ने निषिद्ध गुणवत्ता या चरित्र की शिकायत की। इसके दायरे को विषय-वस्तु और उस संदर्भ के संदर्भ में माना जाना चाहिए जिसमें यह शब्द होता है, कानून के दायरे और उस सार्वजनिक उद्देश्य के संबंध में जो यह सेवा करना चाहता है। पुलिस सेवा एक अनुशासित सेवा है और इसे सख्त अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में ढिलाई सेवा में अनुशासन को नष्ट करती है जिससे कानून और व्यवस्था के रखरखाव में गंभीर प्रभाव पड़ता है।
>
> 7. नियम 16.2(1) में दो भाग हैं। पहला भाग कदाचार के गंभीरतम कृत्यों से संबंधित है जिसमें बर्खास्तगी का आदेश देना शामिल है। निस्संदेह गंभीरतम कदाचार और गंभीरतम कदाचार के बीच अंतर है। बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले यह अनिवार्य होगा कि बर्खास्तगी का आदेश केवल तभी दिया जाना चाहिए जब कदाचार के गंभीर कृत्य हों, क्योंकि यह लंबे समय तक सेवा करने के बाद अपराधी के पेंशन संबंधी अधिकारों का हनन करता है। जैसा कि कहा गया है पहला भाग कदाचार के गंभीरतम कृत्यों से संबंधित है। सामान्य धारा अधिनियम के तहत

एकवचन में बहुवचन शामिल है, "अधिनियम" में अधिनियम शामिल हैं। यह तर्क कि बर्खास्तगी देने के लिए कदाचार के कृत्यों की बहुलता होनी चाहिए, निराधार है। "कार्य" शब्द में एकवचन "कार्य" भी शामिल होगा। यह शिकायत किए गए कृत्यों की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि इसकी गुणवत्ता, घातक प्रभाव और स्थिति की गंभीरता है जो अपमानजनक 'कार्य' से उत्पन्न होती है। सबसे गंभीर कार्य का रंग आस-पास या उपस्थित परिस्थितियों से पता लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उस अपराधी को लीजिए जिसने लगातार 29 साल की सेवा की और उसका रिकॉर्ड बेदाग रहा; 30वें वर्ष में वह सार्वजनिक धन का गबन करता है या गबन को छुपाने के लिए झूठे अभिलेख बनाता है। उसने केवल एक बार प्रतिबद्ध किया। क्या इसका मतलब यह है कि उसे बर्खास्तगी की सजा नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उस वर्ष तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह अपनी पूरी पेंशन प्राप्त कर सके। उत्तर साफतौर पर ना है। इसलिए, भ्रष्टाचार का एक भी कृत्य कदाचार के सबसे गंभीर कृत्य के रूप में नियम के तहत बर्खास्तगी का आदेश देने के लिए पर्याप्त है।

8. नियम का दूसरा भाग निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव को दर्शाता है जो पुलिस सेवा की अचूकता और पूर्ण अयोग्यता को साबित करता है और अपराधी की सेवा की अवधि और पेंशन के लिए उसके दावे को उचित मामले में ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह तर्क कि दोनों भागों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, हमें अतार्किक लगता है। दूसरा भाग चरित्र में मामूली कदाचार के संदर्भ में है, जो अपने आप में बर्खास्तगी के आदेश की गारंटी नहीं देता है, लेकिन कदाचार के निरंतर कृत्यों के कारण सेवा मनोबल पर घातक संचयी प्रभाव पड़ेगा, जो सुधार का अवसर देने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने का आधार हो सकता है। इसके बावजूद यदि अपराधी अधिकारी सुधार योग्य साबित नहीं होता है और सेवा में बने रहने के लिए पूर्ण रूप से अयोग्य पाया जाता है तो ऐसे अवसर देना, सेवा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, दोषी अधिकारी को बर्खास्त करने के

> बजाय, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निचले ग्रेड या रैंक में पदावनति या निष्कासन की कम सजा का प्रावधान है। पुनः रोजगार की भविष्य की संभावनाओं, यदि कोई हो, को प्रभावित किए बिना सेवा से हटा दिया जाए, तो उसे न्याय मिल सकता है। उदाहरण के लिए उस अपराधी अधिकारी को लीजिए जो आवश्यकता पड़ने पर आदतन ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है। सुधरने का मौका देने के बावजूद वह आए दिन ड्यूटी से गायब रहता है। उन्होंने खुद को बेदाग साबित किया और इस तरह सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य साबित हुए। इसलिए, उनकी लंबी सेवा अवधि और पेंशन के लिए उनके दावे को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है ताकि वह आनुपातिक पेंशन अर्जित करने में सक्षम हो सकें। नियम का दूसरा भाग उस क्षेत्र में संचालित होता है। यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि गंभीर कदाचार के लिए सेवा से बर्खास्तगी के आदेश से ही सभी पेंशन लाभ जब्त हो सकते हैं। इसलिए, 'या' शब्द को "और" के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह विघटनकारी और स्वतंत्र होना चाहिए। दोनों खंडों को जोड़ने वाली सामान्य कड़ी "सबसे गंभीर कृत्य/कदाचार" है।

75. इस न्यायालय ने पाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि पुलिस सेवा एक अनुशासित सेवा है और इसमें सख्त अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है। इस संबंध में ढिलाई से सेवा में अनुशासन समाप्त हो जाता है जिससे कानून एवं व्यवस्था के रखरखाव पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

76. इस न्यायालय ने पाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट किए गए **[(2005)8 एससीसी 351] एम. एम. मल्होत्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य** के मामले में फिर से कदाचार के अर्थ और दायरे पर विचार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के एक कार्यालय के अशोभनीय और अपमानजनक आचरण पर विचार करते हुए पाया कि एक व्यक्ति का ऐसी महिला के साथ रहना जो विधिक रूप से शादीशुदा नहीं थी या विवाह के दौरान किसी अन्य महिला के साथ रहना और ऐसी महिला के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना और उसे प्रताड़ित करना अपमानजनक आचरण है। यह न्यायालय निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफों को उद्धृत करना उचित समझता है, जो इस प्रकार हैं: -

"16.सामान्य तौर पर अनुशासनात्मक नियमों की योजना उस आचरण की पहचान करना है जिसे दंडनीय बनाया गया है और फिर उन विभिन्न दंडों का प्रावधान करना है जो ऐसे आचरण से असंगत कार्यों के लिए लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो आचरण के मानकों से संबंधित हैं जिनका सरकारी सेवक (उन नियमों के अर्थ के भीतर) को पालन करना होता है जबकि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम , 1965 कदाचार के लिए दी जाने वाली सज़ा या जुर्माने का प्रावधान करता है। आचरण नियम और दंड के नियम अलग-अलग नियमों में प्रदान किए जा सकते हैं या एक में जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा, कई विभागीय निर्देश हैं जो कर्मचारियों के आचरण के संबंध में स्पष्ट, विस्तृत और दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

17. ऐसी गतिविधियों की श्रेणी जो सार्वजनिक सेवा के हित के साथ असंगत हो सकती हैं और लोक सेवक की स्थिति, स्थिति और गरिमा के अनुरूप नहीं हैं, इतनी विविध हैं कि नियोक्ता के लिए ऐसे कृत्यों को पूरी तरह से गिनना और कदाचार की श्रेणियों को बंद मानना असंभव होगा। इसलिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 'कदाचार' शब्द सटीक परिभाषा देने में सक्षम नहीं है। लेकिन एक ही समय में हालांकि सटीक परिभाषा में असमर्थ है, प्रतिबिंब पर 'दुराचार' शब्द संदर्भ, प्रदर्शन में अपराध और अनुशासन और कर्तव्य की प्रकृति पर इसके प्रभाव से अपना अर्थ प्राप्त करता है। शिकायत किए गए अधिनियम में निषिद्ध गुणवत्ता या चरित्र होना चाहिए और इसके दायरे को विषय-वस्तु और उस संदर्भ के संदर्भ के संदर्भ में माना जाना चाहिए जिसमें यह शब्द होता है, कानून के दायरे और उस सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसे यह सेवा करना चाहता है।

18. सेना नियमों के नियम 14 की पृष्ठभूमि में, रिपोर्ट किए गए भारत संघ और अन्य बनाम वी. हरजीत सिंह संधू, [(2001)5 एससीसी 593], यह माना गया था कि कोई भी गलत कार्य या अपराध का कोई भी कार्य

जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो भी सकती है और नहीं भी, नियम 14 के तहत 'कदाचार' होगा।

19. बलदेव सिंह गांधी बनाम पंजाब सरकार और अन्य [(2002)3 एससीसी 667] में यह माना गया कि अभिव्यक्ति 'कदाचार' का अर्थ गैरविधिक व्यवहार, दुर्व्यवहार, गलत आचरण, दुष्कर्म आदि है।

20. इसी प्रकार, पंजाब सरकार और अन्य में बनाम राम सिंह पूर्व. कांस्टेबल, [(1992)4 एससीसी 54] में यह माना गया कि 'कदाचार' शब्द में नैतिक अधमता शामिल हो सकती है। यह अनुचित या गलत व्यवहार, गैरविधिक व्यवहार, चरित्र में जानबूझकर, निषिद्ध कार्य, कार्रवाई के स्थापित और निश्चित नियम या आचार संहिता का उल्लंघन होना चाहिए, लेकिन केवल निर्णय की त्रुटि, लापरवाही या कर्तव्य के प्रदर्शन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए; अधिनियम में भालू के निषिद्ध गुण या चरित्र की शिकायत की गई।

21. 'कदाचार' जैसा कि बैट के लॉ ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट (चौथा संस्करण) (पेज 63 पर) में कहा गया है, "इसमें सकारात्मक कार्य शामिल हैं, न कि केवल उपेक्षा या असफलता।" बैलेंटाइन लॉ डिक्शनरी (148वें संस्करण) में दी गई इस शब्द की परिभाषा है, "कार्रवाई के कुछ स्थापित और निश्चित नियम का उल्लंघन, जहां आवश्यकता की मांग के अलावा कोई विवेक नहीं बचा है, यह निश्चित कानून का उल्लंघन है, एक निषिद्ध कार्य है. यह लापरवाही से अलग है।"

22. आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के आचरण नियम उनके सेवकों के अनुमेय कार्यों और व्यवहार का एक कोड बनाते हैं।

77. इस न्यायालय ने पाया कि, मामले के वर्तमान तथ्यों में, माना जाता है कि अपीलार्थी अनुशासित पुलिस बल में काम कर रहा था और जब वह एक महिला के साथ सरकारी आवास में रह रहा था, जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ काफी समय से विवाहित थी और ऐसी महिला के साथ उसने अपनी पत्नी जैसा व्यवहार किया और साथ ही, उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी अपने साथ नहीं रखा और इस प्रकार,

अनुशासनात्मक प्राधिकारी सही निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अपीलार्थी द्वारा अनैतिक जीवन जीने और साथ ही अनुशासनहीनता का गंभीर कदाचार किया गया था।

78. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह कहना कि अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे, इस न्यायालय द्वारा यह कहने के लिए पर्याप्त है कि आरोप-पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी पर विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया था कि उसकी शादी सुलोचना नाम की लड़की के साथ हुई थी। और उनके विवाह से पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। अपीलार्थी पर आरोप था कि वह पिछले चार साल से एक महिला के साथ रह रहा था जो सीआरपीएफ, नई दिल्ली में कांस्टेबल है। अपीलार्थी का उस महिला के साथ अवैध संबंध था, जो पहले से शादीशुदा थी और अपीलार्थी उसके साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहा था। उक्त आरोप को किसी भी तरह से अस्पष्ट आरोप नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार, अपीलार्थी के अधिवक्ता की दलील खारिज होने योग्य है।

79. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने बिना सोचे-समझे और सजा का आदेश अनुमानों पर पारित किया गया था, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट पर विचार किया जहां जांच अधिकारी ने नौ व्यक्तियों के बयान दर्ज किए थे और पूरे जांच रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी अपने खिलाफ लगाए गए आरोप का दोषी था और इस प्रकार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कोई यांत्रिक आदेश पारित नहीं किया है, जिसे दिमाग का उपयोग न करने से पीड़ित कहा जा सकता है।

80. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि यह राय बनाने के लिए कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य नहीं था कि अपीलार्थी किसी अन्य विवाहित महिला के साथ संबंध में रह रहा था और केवल सुनी-सुनाई साक्ष्य-गपशप थी, इस न्यायालय ने दर्ज किए गए बयान पर गौर किया। पूछताछ के दौरान, पाया गया कि महिला के पति, जिस पर अपीलार्थी के साथ पत्नी के रूप में रहने का आरोप था-सीता राम से पीडब्लू-1 के रूप में जांच की गई, अपीलार्थी के ससुर से पीडब्लू-2 के रूप में जांच की गई और अपीलार्थी के अन्य पड़ोसियों से पूछताछ की गई। राम देव-पीडब्लू-3, राधा कृष्ण-पीडब्लू-4 और रतनलाल-पीडब्लू-5 के रूप में जांच की गई, उन्होंने यह भी बताया कि अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि किसी अन्य महिला के साथ रह रहा था। अपीलार्थी की पत्नी से पीडब्लू-6 के रूप में पूछताछ की गई और अपीलार्थी की पत्नी के भाइयों से पीडब्लू-7 और

पीडब्लू-8 के रूप में जांच की गई।

81. इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे और इस तरह, यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच अधिकारी के पास अपनी राय बनाने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं था।

82. अपीलार्थी के अधिवक्ता की दलील कि उस महिला के पति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है, जिस पर अपीलार्थी के साथ रहने का आरोप है और इस तरह, उस महिला के पति की शिकायत के अभाव में, अनुशासनात्मक जांच आरंभ नहीं की जानी चाहिए। इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी के ससुर ने शिकायत की थी कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को अपने गृह नगर में छोड़ दिया था और अपीलार्थी एक अन्य कांस्टेबल (मुकेश कुमारी) के साथ व्यभिचारी जीवन जी रहा था। नियोक्ता को अपीलार्थी के ऐसे कदाचार के बारे में सूचित किया जा रहा है, इसलिए अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई है। यह दलील खारिज की जा सकती है कि केवल पत्नी का पति ही व्यभिचार की शिकायत कर सकता है, क्योंकि नियोक्ता को यह देखना होगा कि कर्मचारी आचरण नियमों का पालन करता है या नहीं और उसका उल्लंघन भी नहीं करता है।

83. अपीलार्थी के अधिवक्ता की दलील कि पूरी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करके आयोजित की गई थी, इस न्यायालय ने पाया कि हर चरण में, अपीलार्थी को अनुशासनात्मक जांच में भाग लेने के लिए नोटिस भेजा गया था और यहां तक कि जब अपीलार्थी जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो समाचार-पत्रनोटिस भी प्रकाशित किए गए थे।

84. इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी ने निर्धारित समय के भीतर आरोप-पत्र का उत्तर भी दाखिल नहीं किया और उसके अनुरोध पर समय भी बढ़ाया गया।

85. इस न्यायालय ने मामले के रिकॉर्ड से यह भी पाया कि अपीलार्थी स्वयं जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, उसे प्राप्त जांच रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की और इसके अलावा, वह आरोप की सेवा के बाद भी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी का अनुशासनात्मक कार्यवाही में भाग न लेने और कर्तव्य से अनुपस्थित रहने का अड़ियल रवैया, अपीलार्थी के आचरण और उसके कर्तव्य के प्रति समर्पण के बारे में बहुत कुछ बताता है।

86. अपीलार्थी के अधिवक्ता की यह दलील कि अपीलार्थी पर लगाई गई सजा कठोर और

अनुपातहीन है, इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी के खिलाफ अनैतिक जीवन जीने का गंभीर आरोप लगाया गया था और वह अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते अनैतिक जीवन जी रहा था। जीवन और इस प्रकार, सज़ा को कल्पना के किसी भी स्तर से कठोर नहीं माना जा सकता है।

87. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह कहना कि अपीलार्थी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का लगाया गया आरोप गलत तरीके से दर्ज किया गया था, क्योंकि अपीलार्थी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि अपीलार्थी ने किसी भी समय इसकी जानकारी भी नहीं दी थी। चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन या विभाग को स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की सूचना दी गई है और इस प्रकार, इस भ्रामक याचिका को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

88. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **केशरी मल (सुप्रा.)** के मामले में पारित एक निर्णय पर भरोसा किया है। इस न्यायालय ने पाया कि न्यायालय के समक्ष मुद्दा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के संबंध में था, इसलिए कारण बताओ नोटिस दिया गया। अपराधी सरकारी सेवक को खुले दिमाग से यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि सरकारी सेवक अपने ऊपर लगे आरोपों का दोषी है। आरोप-पत्र में प्रस्तावित सज़ा का भी उल्लेख किया गया था और इस प्रकार, सरकारी कर्मचारी का मामला पूर्वाग्रह से ग्रसित पाया गया।

मामले के वर्तमान तथ्यों में, आरोप-पत्र में कहीं भी अपीलार्थी को दोषी नहीं पाया गया है और आरोप के साथ केवल एक ज्ञापन अपीलार्थी को सूचित किया गया था और इस प्रकार, उक्त निर्णय अपीलार्थी के अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता है।

89. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **छीतरमल** (सुप्रा.) के मामले में पारित एक निर्णय पर भरोसा किया है, इस न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त मामले में, बर्खास्तगी के आदेश पारित करने के बाद जांच रिपोर्ट की प्रति अपराधी को प्रदान की गई थी। बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया गया। वर्तमान मामले के तथ्यों में इस मामले की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

90. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **अनिल गिलुर्कर** (सुप्रा.) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय पर भरोसा किया है। इस न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने ऋण खातों या नामों का विवरण नहीं दिया था। उधारकर्ताओं, स्वीकृत, वितरित और कथित रूप से दुरूपयोग किए गए ऋणों की राशि और

इस तरह, चूंकि आरोप अस्पष्ट थे, इसलिए उन्हें अलग रखा गया था।

मामले के वर्तमान तथ्यों में, आरोप अस्पष्ट नहीं हैं और इस प्रकार, उक्त निर्णय से कोई सहायता नहीं मिलती है।

91. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **इलाहाबाद बैंक और अन्य** (सुप्रा.) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा जताया है। इस न्यायालय ने पाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यदि तथ्यों की खोज को किसी भी साक्ष्य द्वारा असमर्थित दर्ज किया गया था या ऐसा निष्कर्ष जिस पर कोई उचित व्यक्ति नहीं पहुंच सका, तो रिट अदालत मामले की जांच करने और राहत प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होने पर भी उचित होगी।

मामले के वर्तमान तथ्यों में, उचित साक्ष्य दिए गए हैं और तदनुसार जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अपनी राय बनाई और इस प्रकार, यह निर्णय अपीलार्थी के अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता है।

92. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **क्रांति एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड** (सुप्रा.) के मामले पर भरोसा किया है, इस न्यायालय ने पाया कि उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत निर्धारित किए हैं कि कैसे, कारणों को न्यायिक द्वारा दर्ज किया जाना है और अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकाय द्वारा भी। इस न्यायालय ने पाया कि मामले के वर्तमान तथ्यों में, अधिकारियों ने निर्णय लेने के लिए उचित कारण बताए हैं और इस प्रकार, उक्त निर्णय अपीलार्थी के अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता है।

93. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए **दीनानाथ शांताराम कारेकर** (सुप्रा.) के मामले में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया है कि जांच रिपोर्ट अपराधी को प्रदान की जानी आवश्यक है, इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था समय-समय पर और एक विशेष संदेशवाहक भेजकर उन्हें अतिरिक्त प्रतियां प्रदान की गईं और यहां तक कि पेपर प्रकाशन भी किया गया, ऐसे में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान नहीं की गई थी और इसके अलावा, अपीलार्थी को भी नहीं दी गई थी। अनुरोध किया गया कि जांच रिपोर्ट के अभाव में उनके साथ पक्षपात किया गया है। उक्त मामला अपीलार्थी के अधिवक्ता के लिए कोई सहायता नहीं है।

94. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **ज्ञान चंद चत्तर** (सुप्रा.) के मामले में पारित एक निर्णय पर भी भरोसा किया है। उक्त निर्णय विधिक प्रस्ताव पर है कि केवल सुनी-सुनाई बातों पर, अधिकारियों को अपना मन नहीं बनाना चाहिए और गवाहों की आवश्यकता है। जांच अधिकारी के समक्ष जांच की जाएगी। इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में, जांच अधिकारी के समक्ष उचित विधिक साक्ष्य पेश किए गए हैं और इस प्रकार, अपीलार्थी के अधिवक्ता को कोई सहायता नहीं दी जा सकती है।

95. यह न्यायालय, **अजय कुमार श्रीवास्तव** (सुप्रा.) के मामले में, विभागीय जांच में न्यायिक समीक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करना उचित समझता है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा निम्नलिखित उद्धरण हैं:-

> "24. इस प्रकार यह तय हो गया है कि संवैधानिक न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है, न कि निर्णय की योग्यता। यह साधन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है न कि निष्कर्ष की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए। न्यायालय/न्यायाधिकरण अपराधी के खिलाफ की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है यदि यह किसी भी तरह से प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत है या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन है या जहां प्राधिकारी यदि बिना किसी साक्ष्य के आधार पर हो, अनुशासनात्मक निष्कर्ष या निष्कर्ष पर पहुंचा गया है । यदि निष्कर्ष ऐसा हो जिस पर कोई भी उचित व्यक्ति कभी नहीं पहुंच पाया हो या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पहुंचाए गए साक्ष्य पर विचार करने पर निष्कर्ष विकृत हो या रिकॉर्ड पर पेटेंट त्रुटि से ग्रस्त हो या किसी भी सबूत पर आधारित न हो, सर्टिओरीरी रिट जारी की जा सकती है। संक्षेप में, न्यायिक समीक्षा का दायरा तथ्य के रूप में प्राधिकारी के निर्णय की शुद्धता या तर्कसंगतता की जांच तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
>
> 25. जब लोक सेवक के खिलाफ कथित कदाचार के लिए अनुशासनात्मक जांच की जाती है, तो न्यायालय को जांच और निर्धारण करना होता है:

(i) क्या जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थी;

(ii) क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का अनुपालन किया जाता है;

(iii) क्या निष्कर्ष या निष्कर्ष कुछ सबूतों पर आधारित हैं और प्राधिकारी के पास तथ्य या निष्कर्ष तक पहुंचने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है।

26. यह अच्छी तरह से तय है कि जहां जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं है, वहां जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी पूर्व द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत हो भी सकता है और नहीं भी, असहमति की स्थिति में अनुशासनात्मक प्राधिकारी को ऐसा करना होगा। असहमति के कारणों को रिकॉर्ड करें और अपराधी को सुनवाई का अवसर देने के बाद यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य इस तरह के अभ्यास के लिए पर्याप्त हैं तो वह अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है या फिर मामले को आगे की जांच के लिए जांच अधिकारी को भेज सकता है।

27. यह सच है कि साक्ष्य के सख्त नियम विभागीय जांच कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, कानून की एकमात्र आवश्यकता यह है कि अपराधी के खिलाफ आरोप ऐसे सबूतों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक उचित व्यक्ति उचित और निष्पक्षता के साथ दोषी कर्मचारी के खिलाफ आरोप की गंभीरता को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंच सके। यह सच है कि केवल अनुमान या अटकलें विभागीय जांच कार्यवाही में भी अपराध की पुष्टि को कायम नहीं रख सकतीं।

28. संवैधानिक न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136 के तहत न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, दुर्भावना या विकृति के मामले को छोड़कर, अर्थात जहां ऐसा हो, विभागीय जांच कार्यवाही में आए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है या जहां कोई निष्कर्ष ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति तर्कसंगत और निष्पक्षता के

साथ काम करके उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है और जब तक विभागीय प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत हैं, तब तक वही होना चाहिए निरंतर।"

96. इस न्यायालय ने पाया कि अधिकारियों ने अपीलार्थी के खिलाफ जांच शुरू करने और सेवा से बर्खास्तगी की सजा देकर आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

97. इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान रिट याचिका में कोई विशेषता नहीं है अतः, इसे खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

हिमांशू सोनी/392

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।